भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5409

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

मुल्लापेरियार के बेबी डैम को मजबूत करने और विकसित करने के लिए वृक्षों को हटाना

5409. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मुल्लापेरियार के बेबी डैम, जो कि 240 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है, पर लगभग 27 विशाल वृक्ष खड़े हैं, जो मुख्य बांध के समानांतर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य बांध में जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोकना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त बेबी डैम को मजबूत करने और विकसित करने के लिए इन 27 विशाल पेड़ों को गिराने के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): मुल्लापेरियार बांध में एक संरेखण में मुख्य बांध, प्राकृतिक टीला(नेचुरल माउंड), बेबी डैम और मृदा बांध शामिल हैं। बेबी डैम मुख्य बांध के समानांतर नहीं है। बेबी डैम की ऊंचाई 53 फीट है और नीचे की तरफ चौड़ाई 38 फीट और ऊपर की तरफ 12 फीट है और लंबाई 240 फीट है। बेबी डैम और मृदा बांध बाएं किनारे पर हैं और स्पिलवे दाहिने किनारे पर है, जो स्वीकार्य भंडारण स्तर से ऊपर अतिरिक्त पानी के प्रवाह के लिए है। बेबी डैम जलाशय में पानी के भंडारण के लिए है। बेबी डैम के अनुप्रवाह क्षेत्र में कोई विशाल पेड़ नहीं हैं, केवल 15 मध्यम और छोटे पेड़ मौजूद हैं, जैसा कि मुल्ला पेरियार बांध के लिए पर्यवेक्षी समिति द्वारा अपने विभिन्न पत्राचार में और साथ ही दिनांक 04.07.2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका संख्या 880/2020 के संबंध में पर्यवेक्षी समिति द्वारा दायर हलफनामे में पुष्टि की गई है।

बेबी डैम और मृदा के बांध को मजबूत करने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2006 के अंतरिम आदेश में दिया गया था और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के निर्णय में भी दोहराया गया था।

हालाँकि, बेबी डैम और मृदा बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि बेबी डैम के नीचे की ओर पेड़ों को काटने के लिए केरल सरकार द्वारा पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी गई थी।

तमिलनाडु सरकार ने बेबी डैम के नीचे पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए वर्ष 2015 में परिवेश 1.0 पोर्टल पर आवेदन किया था; और, वर्ष 2021 में अनुमति प्रदान की गई थी। हालाँकि, कुछ ही दिनों में अनुमति रद्द कर दी गई। केरल सरकार ने तमिलनाडु सरकार से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश 2.0 पोर्टल पर अनुमति के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अनुरोध किया है।

*****